

No. 2(6)/2007-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 21st September, 2007.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Upgradation of Bangalore as A-1 class city for the purpose of House Rent Allowance/Compensatory (City) Allowance – regarding.

The undersigned is directed to invite attention to this Ministry's O.M. No.2(21)/E.II(B)/2004 dated 18.11.2004 regarding re-classification/upgradation of cities on the basis of the population figures of 2001 census for the purpose of House Rent Allowance/Compensatory (City) Allowance to the Central Government employees and to say that consequent upon re-constitution of the area of Bangalore Mahanagara Palike and re-naming it as Bruhat Bangalore Mahanagara Palike with the addition of certain areas within its Municipal limits vide Notification no. UDD 92 MNY 2006 dated 16.01.2007 of the Government of Karnataka, the population of 'Bruhat Bangalore Mahanagara Palike' has increased, and therefore qualifies for classification as 'A-1' class city for the purpose of House Rent Allowance/ Compensatory (City) Allowance to the Central Government employees.

2. The President is, accordingly, pleased to decide that the city of Bangalore (including existing Urban Agglomeration) shall stand classified as 'A-1' class city for the purpose of grant of House Rent Allowance/Compensatory (City) Allowance to the Central Government employees posted there.

3. These orders shall be effective from 1st October, 2007.

4. The orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also be applicable to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

(R. Prem Anand)

(R. Prem Anand)

Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

सं. 2(6)/2007-संस्था-II(ख)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता के प्रयोजनार्थ बंगलौर का ए-I श्रेणी के शहर के रूप में स्तरोन्नयन।

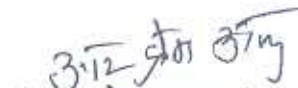
अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन से 2001 की जनगणना के आधार पर शहरों के पुनःवर्गीकरण/स्तरोन्नयन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं. 2(21)/संस्था-II(ख)/2004 की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्नाटक सरकार की दिनांक 16.01.2007 की अधिसूचना संख्या यू.डी.डी. 92 एम.एन.वाई. 2006 के द्वारा बंगलौर महानगर पालिका क्षेत्र के पुनर्गठन तथा इसकी नगर सीमा में कतिपय क्षेत्रों को जोड़ने से इसका बृहत् बंगलौर महानगर पालिका के रूप में पुनः नामकरण किए जाने के फलस्वरूप, "बृहत् बंगलौर महानगर पालिका" की जनसंख्या बढ़ गई है और इस प्रकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के प्रयोजन से इसने "ए-I" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकरण हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।

2. तदनुसार, राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि यहां तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बंगलौर (मौजूदा नगर बस्तियों सहित) "ए-I" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत माना जाएगा।

3. ये आदेश 01 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी होंगे।

4. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें रक्षा सेवा आकलनों से भुगतान किया जाता है। सशस्त्र बल के कार्मिकों एवं रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।


(आर.प्रेम आनन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।